भारत में रोजगार की स्थिति – एक राजनीतिक वृत्तांत

डॉ० हरीश कुमार
एसोसिएट प्रोफेसर
विज्ञान विभाग
एम०एम० (पी०जी०) कॉलेज, मोदीनगर, गाजियाबाद (उ०प्र०)
ईमेलः kumarharish0430@gmail.com

सारांश

अब असमानता के नकारात्मक परिणामों की बेहतर समझ बन चुकी है। साथ में इस बारे में भी बेहतर समझ बनी है कि किस तरह की आर्थिक संवृद्धि असमानताओं की ओर ले जाती हैं। विश्व भर में किए गए हाल के अनुसंधान से यह सामने आया है कि निरंतरता से बनी हुई अधिक असमानता दीर्घ–कालीन आर्थिक संवृद्धि को कम करती है कि निरंतरता से बनी हुई अधिक असमानता दीर्घ–कालीन आर्थिक संवृद्धि को कम करती है। इसका एक पक्ष यह है कि असमानता निर्धन लोगों के लिए शिक्षा के अवसर कम करती है। इसका एक पक्ष यह है कि असमानता निर्धन लोगों के लिए शिक्षा के अवसर कम करती है, इस कारण मानवीय पूँजी का गुणात्मक और संख्यात्मक प्रसार दब जाता है व तकनीकी विशेष कुषलताओं का प्रयास भी बाधित होता है। विषमता का किसी निर्धन व्यक्ति के स्वास्थ पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है व इस कारण उसकी उत्पादकता कम हो सकती है। इस तरह भी आर्थिक संवृद्धि कम हो सकती है। विषमता पर पर्याप्त ध्यान देने से ही अब नीतियों का विमर्श 'समावेशी संवृद्धि' की ओर बढ़ा है।

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 26.08.2022
Approved: 17.09.2022

डॉ० हरीश कुमार

भारत में रोजगार की स्थिति – एक राजनीतिक वृत्तांत

RJPP Apr.22-Sept.22, Vol. XX, No. II,

pp.311-317
Article No. 40

Online available at :
https://anubooks.com/rjpp-2022-vol-xx-no-2

अर्थव्यवस्था में रोजगार विहीन संवृद्धि की स्थति में असमानता का अध्ययन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, विशेषकर जब जिन रोजगारों का सृजन हो रहा है वह भी मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में हो रहा है या संगठित क्षेत्र में अनौपचारिक रोजगार के रूप में हो रहा है। यह स्थिति विशेषकर परेशान करने वाली है क्योंकि यह आर्थिक संवृद्धि की एक लुभावनी तस्वीर सामने रखती है। भारत एक निर्धन देश है व यह भी सामाजिक सुरक्षा कवच से वंचित। इसके करोड़ों नागरिकों के लिए कुछ न कुछ रोजगार तो प्राप्त करना बहुत जरूरी है। शायद इस कारण बेरोजगारी के आंकड़े अपेक्षाकृत कम नजर आते हैं।

अधिसंख्य भारतीयों के लिए अब चुनौती गुजर–बसर की नहीं है, अपितु आकंक्षाओं की भी है। श्रम व रोजगार मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2017–18 कहती है। ''रोजगार सभी के दैनिक जीवन का हिस्सा है।'' इस तरह सरकार की सोच में भी अच्छे, सम्मानजनक, 'डीसेंट' रोजगारों के माध्यम से गरिमा प्राप्त करने की बात है, पर वास्तविकता इससे बहुत अलग है व ऐसे दृश्यों में नजर आती है जैसे कि सफाईकर्मी के कार्य के लिए किसी इंजीनियर का आवेदन करना। आकाक्षा प्रेरित भारतीयों के लिए यह पर्याप्त नहीं है कि कोई भी रोजगार मिल जाए, उन्हें अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुरूप अच्छा, डीसेंट रोजगार चाहिए, पर इस तरह का रोजगार मिलना बहुत कठिन हो रहा है। किसी भी तरह का रोजगार मजबूरी में स्वीकर कर लेना व ऐसा रोजगार प्राप्त करना जो आकांक्षाओं व योग्यताओं के अनुकूल हो यह दो स्थितियाँ बहुत अलग है, पर भारत में तो फिलहाल दोनों स्तरों पर विफलता नजर आ रही है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2017 में स्वीकार किया गया, 'भारत अपनी बढ़ती हुई श्रम शक्ति की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हिुत कम रोजगारों का सृजन कर पाता है, व इस कारण अनेक व्यक्ति कामगार शक्ति से बाहर रह जाते हैं, अनेकों को अर्द्ध या अल्प–रोजगार मिलता है व अनेक को बहुत कम मजदूरी या आय मिलती है।

वर्ष 2014 के अपने चुनाव घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने प्रति वर्ष एक करोड़ रोजगार सृजन करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया जिसे अनेक युवा मतदाताओं ने आकर्शित किया जो शायद स्वयं भी रोजगार ढूंढ रहे थे। पांच वर्ष बाद यह लक्ष्य प्राप्ति से बहुत दूर है। विश्व बैंक के अनुसार, पहले जैसे रोजगार को बनाए रखने के लिए भारत में एक वर्ष में 80 लाख रोजगारों का सृजन होना चाहिए (दास 2019)। वर्ष 2004–05 और 2011–12 के बीच भारत ने गैर–कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष 75 लाख रोजगारों का सृजन किया। 2011–12 और 2015–16 के बीच सरकार प्रति वर्ष मात्र 22 लाख रोजगारों का सृजन कर सकी। (मेहरोत्रा 2010)

बढ़ती हुई बेरोजगारी

नवीनतम अप्रकाशित श्रम ब्यूरों के आंकड़ों के अनुसार (सरकार ने अधिकृत तौर पर अभी इन आंकड़ों को स्वीकार नहीं किया है) वर्ष 2017–18 में बेरोजगारी चार दशकों के अधिकतम स्तर 6.1 प्रतिशत पर पहुंच गई। सरकार द्वारा विमुद्रीकरण के बाद के चार वर्षों में यह उच्चतम स्तर पर पहुंची है (झा 2019 ए)। महेश व्यास (2018 ए) सेंटर फार मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकॉनोमी (सी0एम0आई0ई0) के अनुसार विमुद्रीकरण से पहले श्रम–भागेदारी 47 प्रतिशत थी पर विमुद्रीकरण के बाद अगस्त 2018 में यह 42.5 प्रतिशत पर पहुंच गई। इसका अर्थ यह है कि लगभग 4 प्रतिशत रोजगार की आयु की जनसंख्या विमुद्रीकरण के बाद श्रम–शक्ति से बाहर हो गई। इनमें से अधिकांश महिलाएं थी। महिलाओं का श्रम–शक्ति में भागेदारी का कम होना एक गंभीर समस्या है।

कामगारों के लिए रोजगारों की घटती गुणवत्ता

उदारीकरण आरंभ होने के बाद के दौर में अधिकतर रोजगारों का सृजन सेवा (सर्विस) क्षेत्र में हुआ। पर यह पर्याप्त नहीं रहा। औद्योगिक (मैनुफैक्चरिंग) व सेवा क्षेत्र में बढ़ते मशीनीकरण का अर्थ यह है कि अनेक रोजगार लुप्त हो रहे हैं। जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड में एक अरब डालर के निवेश से दस लाख टन स्टील बनाने का संयंत्र लगा है पर इसमें मात्र 5000 कामगारों को रोजगार मिलता है। 5 वर्ष पहले इतने बड़े संयंत्र में 9000 कामगारों को रोजगार मिलता। (दास 2019)

अर्थव्यवस्था अपर्याप्त रोजगार सृजन व कम गुणवत्ता के रोजगारों की दो समस्याओं से जूझ रही है। इस कारण ऐसे लोगों की निर्धनता बढ़ रही है जो रोजगार तो कर रहे हैं पर जिनकी आय गरीबी रेखा से नीचे है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट विश्व रोजगार सामाजिक आऊटलुक–ट्रेन्डस (2018) के अनुसार जहाँ कुछ सूचना संचार व तकनीकी –सघन (आई0सी0टी0) सेवाओं में मजबूत रोजगार सृजन हुआ है, विशेषकर भारत में, पर सेवा क्षेत्र में पिछले कुछ दशकों में अधिकतर रोजगारों का सृजन पुरानी, कम मूल्य वृद्धि करने वाली सेवाओं में हुआ है, जहां अनौपचारिकता व असुरक्षित रोजगार अधिक है।

रोजगार सृजन पर रोजगार–सुरक्षा नहीं

यह कोई अस्थाई स्थिति नहीं है अपितु व्यवस्थित तौर पर सरकारी नीति में बदलाव है। वर्ष 2018 के बजट भाषण में वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कहा कि सरकार सभी औद्योगिक क्षेत्रों में निश्चित अवधि के अनुबंध के रोजगारों की नीति अपना रही है। इसका उद्देश्य अधिक तेजी से रोजगारों का सृजन बताया गया, पर इससे सरकारी नीति में रोजगार सुरक्षा से रोजगार सृजन की ओर बदलाव का संकेत मिला व इससे रोजगारों की गुणवत्ता उपेक्षित होती है। रोजगारों की गुणवत्ता में रोजगारों की दीर्घकालीन अवधि व सुरक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है, इस समझ का कि जब तक कोई विशेष नई परिस्थति न हो रोजगार बना रहेगा व इसके साथ विभिन्न रूपों में सामाजिक सुरक्षा व अन्य लाभ जुड़े रहेंगे (जैसे बीमा, पेंशन, ग्रेचयुटी आदि)।

एन0एस0एस0ओ0 के अनुसार केवल एक तिहाई भारतीय मजदूरों के पास कोई लिखित अनुबंध है। 28 प्रतिशत मजदूर ही संगठित मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र में है और उनमें से अनेक के रोजगार में सुरक्षा कम हुई है। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2000 और 2013 के बीच संगठित मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र की कुल श्रम शक्ति में ठेके के मजदूरों का हिस्सा लगभग दोगुना हो गया है। अन्यत्र हमने बताया है कि किस तरह ठेके के कामगार एक स्थाई रोजगार वाले व्यक्ति से एक तिहाई से भी कम आय अर्जित करते हैं। इससे आय व कार्य की गुणवत्ता में असमानता उत्पन्न होती हैं अब तो सरकारी सेवाओं में भी डाक्टरों, नर्सों व अध्यापकों के अनुबंध की शर्तों पर कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ी हैं।

श्रम मंत्रालय के पांचवे वार्षिक रोजगार व बेरोजगारों के सर्वेक्षण 2015–16 के अनुसार 77 प्रतिशत भारतीय परिवारों में नियमित वेतन वाला एक भी सदस्य नहीं पाया गया।

एस0डब्ल्यू0आई0 2018 के अनुसार सभी क्षेत्रों में महिलाओं की 16 प्रतिशत स्थिति है पर केवल घरेलू कर्मियों को लें तो इनमें महिलाओं की 60 प्रतिशत उपस्थिति है। इसी तरह अनुसूचित जातियों के सभी कामगारों में 18.5 प्रतिशत उपस्थिति है पर केवल चमड़ा उद्योग कामगारों को दखें तो उनकी उपस्थिति 46 प्रतिशत है। इस उद्योग में कार्य की स्थितियां स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है।

हमें लगता है कि मौजूदा विकास के मॉडल ने देश में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न की है।

रोजगार–सघन मध्यम, छोटे व सूक्ष्म उद्यमों को अधिक महत्त्व देने के स्थान पर पूँजी–सघन विशालकाय परियोजनाओं को महत्व दिया गया व इस कारण बेरोजगारी की समस्या गंभीर हुई। यह गुजरात में भी देखा गया जहां प्रवासी मजदूरों को स्थानीय लोगों ने 2018 में वापस भेजा। इससे यहां के विकास मॉडल के तनाव अभिव्यक्त होते हैं। (लालीवाला व जेजरेलो, 2018)

हमें लगता है कि मौजूदा विकास के मॉडल ने देश में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न की है। रोजगार–सघन मध्यम, छोटे व सूक्ष्म उद्यमों को अधिक महत्व देने के स्थान पर पूँजी–सघन विशालकाय परियोजनाओं को महत्व दिया गया व इस कारण बेरोजगारी की समस्या गंभीर हुई। यह गुजरात में भी देखा गया। जहां प्रवासी मजदूरों को स्थानीय लोगों ने 2018 में वापस भेजा। इससे यहां के विकास मॉडल के तनाव अभिव्यक्त होते हैं (लालीवाला व जेफरेलो, 2018)

बढ़ती बेरोजगारी व निराश युवा

युवाओं में रोजगार के बारे में चिंताएं बढ़ रही है। यह चिंता अनेक युवा सर्वेक्षणों में सामने आई हैं। (बेनीवाल व प्रधान, 2018)

4675 व्यक्तियों में किए गए यूगव– मिंट मिलेनियल सर्वेक्षण 2018 से यह सामने आया कि 18–21 आयु वर्ग में 72 प्रतिशत, 22–28 आयु वर्ग में 65.35 प्रतिशत, 29–37 आयु वर्ग में 52.4 प्रतिशत व 38–53 आयु वर्ग में 59.74 प्रतिशत ने कहा कि इन दिनों रोजगार प्राप्त करना कठिन है। 22–28 आयु वर्ग में डिप्लोमा/कालेज डिग्री या हाई स्कूल पास करने वालों ने बताया कि शहरी केन्द्रों में उनमें से अधिकतर 30000 रूपए प्रति माह से कम आय प्राप्त करते हैं जबकि उनकी अपेक्षा 30000 रूपए प्रति माह प्राप्त करने की है। (कवाटरा, 2018)

अधिक चिंताजनक यह है कि उन शिक्षित युवाओं (15–29 आयु वर्ग) की संख्या बढ़ रही है जो अब 'रोजगार, शिक्षा व प्रशिक्षण' किसी में नहीं हैं। इनकी संख्या वर्ष 2004–05 में 7 करोड़ थी, व वर्ष 2004–05 से 2011–12 तक प्रति वर्ष 20 लाख की औसत से बढ़ती रही। जबकि वर्ष 2011–12 तक प्रति वर्ष 20 लाख की औसत से बढ़ती रही जबकि वर्ष 2011–12 व 2015–16 के बीच उनकी संख्या औसतन प्रति वर्ष 50 लाख की दर से बढ़ी। यदि यह प्रवृत्ति बनी रही तो मेहरोत्रा (2019) को अनुमान है कि वर्ष 2017–18 तक 11.5 करोड़ शिक्षित युवा श्रम–शक्ति से बाहर होंगे। इस तरह युवाओं के जनसंख्या में अधिक प्रतिशत से लाभान्वित होने के स्थान पर एक बड़े संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।

शिक्षा में संकट

इस स्थिति के केन्द्र में भारतीय राज्य की अपने नागरिकों को अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा देने में विफलता है। ब्रिक देशों में भारत का शिक्षा पर खर्च सबसे कम है। इसका परिणाम है स्कूल की शिक्षा की निचले स्तर की गुणवत्ता व उचित शिक्षा ग्रहण न हो पाना।

हालांकि सरकार ने माध्यमिक स्तर पर व्यवसायिक (वोकेशनल) शिक्षा के विस्तार के लिए नए समग्र शिक्षा अभियान को आरंभ किया है, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुभवों से पता चलता है कि रोजगार प्रदान करने वाले ऐसे व्यक्तियों की तलाश करते हैं जो टीम के साथ मिलकर काम करने, समस्याएं सुलझाने व अच्छे संप्रेशण में दक्ष हैं। केवल एक व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त किए व्यक्ति का महत्व उनकी नजरों में अपेक्षाकृत कम है। आर0टी0ई0 कानून तो कक्षा 8 तक अनिवार्य व निशुल्क शिक्षा के लिए बन गया है व इसे कक्षा 10 तक ले जाने की भी चर्चा है, पर अभी स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में बहुत सुधार की जरूरत बनी हुई है।

शिक्षा से रोजगार वृद्धि का पर्याप्त लाभ नहीं

भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे युवा है व उसकी मीडियन आयु 24 वर्ष है। वर्ष 2020 तक भारत की औसत आयु 29 होगी, जबकि चीन में यह 37 होगी व जापान में 48 होगी (दास 2019)। इस समय भारत में सबसे अधिक युवा जनसंख्या है। भारत की 65 प्रतिशत जनसंख्या 15–59 आयु वर्ग यानि रोजगार सक्रियता के आयु वर्ग की है। इस आयु वर्ग की हिस्सेदारी 2035–40 तक बढ़ने की संभावना है व इस कारण अपनी जनसंख्या के आयु वर्ग की स्थिति से लाभान्वित होने की सबसे अधिक संभावनाएं भारत के पास हैं (कपूर, 2019)।

श्रम ब्यूरों के वार्शि सर्वेक्षण के अनुमानों के आधार पर मेहरोत्रा (2019) ने बताया है कि देश में बेरोजगारी की वृद्धि में तेज वृद्धि हुई है। जो मिडल स्कूल पास है उनके लिए बेरोजगारी दर वर्ष 2011–12 में 0.6 प्रतिशत थी, वर्ष 2018 में यह बढ़कर 3.2 प्रतिशत हो गई। इसी तरह कक्षा 12 पास की श्रेणी में इस दौरान बेरोजगारी दर 2 से 4.4 प्रतिशत बढ़ गई। स्नातकों के लिए इस दौरान बेरोजगारी दर 4.1 प्रतिशत से 8.4 प्रतिशत बढ़ गई। स्नातकोत्तर श्रेणी में यह दर 5.3 प्रतिशत से बढ़कर 8.5 प्रतिशत तक पहुंच गई। टेक्नीकल शिक्षा के क्षेत्र में स्नातकों के लिए बेरोजगारी दर 6. 9 प्रतिशत से बढ़कर 11 प्रतिशत तक पहुंच गई, स्नातकोत्तरों के लिए 5.7 प्रतिशत से बढ़ 7 प्रतिशत हो गई व व्यवसायिक प्रशिक्षण की श्रेणी में 4.9 प्रतिशत से 7.9 प्रतिशत तग बढ़ गई इस तरह जितने अधिक शिक्षित हैं उतनी ही बेरोजगारी की संभावना बढ़ जाती है। वर्ष 2016 में मध्य प्रदेश के रोजगार आवेदन कार्यालयों में 12.98 लाख बेरोजगार युवाओं के नाम दर्ज थे।

केवल रोजगार नहीं, अच्छे रोजगार

कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था में गैर–कृषि रोजगार इसकी अपेक्षा कहीं कम सृजित हो रहे हैं जितने कि इस क्षेत्र के लिए संभावित कामगार उपलब्ध हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए वर्ष 2005 के बाद के समय से गैर–कृषि क्षेत्र में मुख्य रूप से निर्माण कार्यों में ही रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं। 2004–05 और 2011–12 के बीच जब भारत की 15–59 आयु वर्ग की जनसंख्या 11.3 करोड़ से बढ़ी, उनमें छात्रों की संख्या 4.15 करोड़ से बढ़ी। ग्रामीण क्षेत्र से युवा बड़ी संख्या में शिक्षा संस्थानों में गए। इस तरह भविष्य में अच्छी गुणवत्ता के रोजगार अपेक्षित करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।

दूसरा भारत

सोशल मीडिया व टेलीविजन में भारतीय समाज की आकांक्षा की सफलता की अनेक बड़ी व आकर्शक कहानियां हैं। हम अम्बानी और बड़े फिल्म सितारों की कहानियों में रूचि लेते हैं, रियलिटी शो देखते हैं जिनमें अचानक करोड़पति बन जाते हैं, मजदूरों या आटो रिक्शा चलाने वालों के बच्चों को आई0ए0एस0 में चयनित होने के बारे में सुनते हैं। इस तरह माहौल बनता है कि ऊपर तक जाने के तमात अवसर खुल हैं, कोई मेहनत करे तो उसको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। (हलर्नकर, 2018)

महिलाओं की गैर–मौजूदगी

पुरूषों की श्रम–शक्ति भागेदारी दर वर्ष 2015–16 में 75.5 प्रतिशत थी व 2016–17 में यह 76.8 प्रतिशत हो गई। महिलाओं के संदर्भ में यह वर्ष 2015–16 में 27.4 प्रतिशत थी व 2016–17 में घटकर 26.9 प्रतिशत हो गई (झा 2019–ए)। इसका अर्थ यह हुआ कि जहां पुरूषों का श्रम–शक्ति में हिस्सा बढ़ रहा है, वहाँ महिलाएं विभिन्न कारणों से इसे छोड़ रही हैं– अच्छे रोजगारों के अभाव

के कारण, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए या महिलाओं के रोजगार के विरूद्ध प्रतिकूल सामाजिक मान्यताओं की वजह से।

विश्व बैंक (2017) के अध्ययन में पाया कि महिलाओं का श्रम–भागेदारी का निर्णय सबसे अधिक घर से आर्थिक स्थिरता से प्रभावित होता है, न कि सामाजिक मान्यताओं, शिखा स्तर व आयु से। दूसरे शब्दों में, अधिक इस अध्ययन के अनुसार वर्ष 2004–05 और 2011–12 के बीच परिवारों में स्थाई आय अर्जित करने वालों का प्रतिशत बढ़ा जबकि स्व–रोजगार या अस्थाई रोजगार को प्रतिशत कम हुआ, जिसे परिवार में बढ़ती आर्थिक स्थिरता का द्योतक माना गया।

रोजगार छोड़ने के बाद महिलाओं की व्यस्तता ऐसे कार्यों में अधिक देखी गई जो परिवार की प्रतिष्ठा स्थापित करने या बढ़ाने से जुडे थे।

शिक्षा का सीमित उद्देश्य

अभिभावक अपनी बेटियों को शिक्षित करने को पहले से अधिक महत्व दे रहे हैं। सिंधु दिल्ली में घरेलू कर्मी है, पश्चिम बंगाल से आई है। उसके गांव में उसके बीमार पति व दो युवा बेटियां हैं। वह एक छोटे से कमरे में दो अन्य महिलाओं के साथ रहती है। वह एक परिवार में 12 घंटे काम करती है व फिर एक अन्य परिवार में कुछ अतिरिक्त आय के लिए पार्ट–टाईम काम भी करती है। वह कहती है– "मैं इस शहर में अपनी बेटी को पढ़ाने आई हूं। वह बहुत होशियार है व प्राईवेट स्कूल में पढ़ती है। मैं उसके लिए व अपनी वृद्धावस्था के लिए यहां आई हूं।

किन्तु माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शिक्षा से जरूरी नहीं कि महिलाओं की श्रम–शक्ति में भागेदारी हो जाएगी। महिलाओं की श्रम–शक्ति में भागेदारी माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त महिलाओं में कम है। यह शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी दर अधिक होने के कारण है। महिलाओं की श्रम–शक्ति में भागेदारी अनपढ़ वर्ग में या स्नातकों में अधिक है। पर इन दो समूहों में भी वर्ष 2004–05 व 2011–12 के बीच भागेदारी में गिरावट आई। साक्षरता आने से जरूरी नहीं है कि परिवार में महिला की निर्णय क्षमता या अधिकार बढ़ते है।

निष्कर्ष व संस्तुतियां

यह स्पष्ट है कि भारत में रोजगार का एक बड़ा संकट है। इस संकट का उचित समय पर समाधान न हुआ तो इसका समाज की स्थिरता और शान्ति पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। एक ओर जो दसियों लाख युवा श्रम–शक्ति में प्रतिवर्ष आ रहे हैं उनके लिए पर्याप्त रोजगार नहीं हैं व दूसरी ओर इन रोजगारों की गुणवत्ता व वेतन अपेक्षा से कहीं कम हैं। लिंग, जाति व धर्म आधारित भेदभावों के कारण भी अनेक युवाओं को रोजगार प्राप्त होने में अतिरिक्त समस्याएं हैं। इस स्थिति से परेशान युवा एक समय के बाद रोजगार की तलाश छोड़ देते हैं। इन कारणों से सरकार द्वारा रोजगार प्राप्ति की सुविधाजनक परिभाषा के बावजूद बेरोजगारी के आंकड़े चिंताजनक हो रहे हैं व यह प्रवृत्ति आगे और बढ़ सकती है। मौजूदा विकास मॉडल के आधार पर हमने अरबपतियों का अभिजात समुदाय बढ़ा दिया है व वर्ष 2017–18 में ऊपर के 1 प्रतिशत लोगों की संपत्ति 39 प्रतिशत बढ़ गई व नीचे के 50 प्रतिशत लोगों की संपत्ति मात्र 3 प्रतिशत बढ़ी (ग्लोबल वैल्थ रिपोर्ट)। 7.8 करोड़ संख्या तक बढ़ता हुआ मध्य आय का समूह भी है पर उसका जनसंख्या में हिस्सा अभी कम ही है। (द इक्नामिस्ट, 2018)। इस तरह जनसंख्या के एक बड़े हिस्से में ऊपर उठने की आकांक्षा तो है पर अपनी मौजूदा कम वेतन व तंग आर्थिक स्थिति के चलते उठ पाने की उसकी क्षमता अभी तक बहुत कम है।

अतः सरकार को यह कदम उठाने होंगे–

1. विकास में प्राथमिकता श्रम–सघन क्षेत्रों को देनी चाहिए ताकि अधिक रोजगारों का सृजन हो।
2. रोजगारों में वृद्धि समावेशी होनी चाहिए। नए रोजगारों में रोजगार सुरक्षा, बेहतर कार्य स्थितियां, सामाजिक सुरक्षा लाभ व संगठन बनाने का अधिकार उपलब्ध रहने चाहिए। इससे कुल उत्पादकता बढ़ेगी व इससे निवेश पर अधिक लाभ मिलेगा।
3. कुशलता बढ़ाने पर बेहतर ध्यान देना चाहिए ताकि अन्तर्राष्ट्रीय सपर्धा में टिक सकें।
4. सरकार को भ्रष्टाचार दूर करना चाहिए। विषमता व बेरोजगारी बढ़ाने वाले अन्य कारकों जैसे याराना पूँजीवाद को नियंत्रित करना चाहिए। कर–नीतियां विषमता दर कम करने वाली होनी चाहिए। कॉरपोरेट टैक्स में छूट देने के अतिरिक्त उत्साह उचित नहीं है। इस तरह जो अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा सुधारने के लिए करना चाहिए।

संदर्भ

1. Andres, Luis A., Gupta, Basab Das., Joseph, George., Abrahim, Vinoj., Correria, Maria. (2017). Precarious Drop: Reassessing Patterns of Female Labor Force participation in India. World Bank Policy Research Working paper No. 8024. South Asia Region: New Delhi. Social Development Unit. World Bank.
2. Basole, Amit., Jayadev, Arjun., Shrivastava, Anand., Abraham, Rosa. (2018). State of Working India. Azim Premji University: Bengaluru.
3. Das, Goutam. (2019). Jobonomics. India"s Employment Crisis and What the Future Holds. Hatchelt India: Gurugram.
4. Economic Times. (2018). "Over 93,000 Candidates, Including 3,700 Ph.D Holders Apply for Peon Job in UP". Economic Times 30 August.
5. Ghosh, Jayali. (2016). "Time Povery and The Poverty of Economics". METu Studies in Development Vol. 43. No. 1.
6. Hensman, Rohini. (2014). "The Gujarat Model of Deveopment : What would it do to the Indian Economy". Economic and political Weekly. Vol. 49. Issue No. 11. 15 March.
7. Jha, Somesh. (2019a). "Unemployment Rate at Four-decade High of 6.1% in 2017-18; NSSO Survey". Business Standard. 6 February.
8. Kant, Amitab., Kapoor, Vaibhav., Nagaich, Ranveer. (2018). "India"s Burgeoning Middle Class". Live Mint. 23 January.
9. Kapoor, Rashicka. (2019). "Squandering India"s Demographic Dividend". Business Standard. 14 February.
10. Sharik, Laliwala., Jaffrelot, Christophe. (2018). "A New Other". Indian Express. 22 october.